(v) The loopholes in the existing protective laws should be plugged.

(vi) The holistic approach with emphasis on economic educational and health programmes for the primitive tribes should be adopted and a Centrally Sponsored scheme for development of Primitive Tribal Groups formulated.

(vii) Development of dispersed tribals should be continued from the funds given out of SCA as an additive and the normal flow out of State Plan funds for the dispersed tribals should also continue.

(c) to (f) The Working Groups and Steering Committees are set up by the Planning Commission at the time of formulation of Five Year Plans. Their recommendations are taken into consideration while formulating the Five Yaer Plans. These Working Groups and Committees are set up as part of the internal exercise to assist the Planning Commission in formulating Plans and Programmes.

Chapter Sixteen of Eighth Five Year Plan (1992—97) Vol. II lays down the strategy and programmes for the development of Sch. Castes and Sch. Tribes, Copies of the Eighth Five Year Plan document have already been placed on the Table of the House.

It may, however, be added that the Report of the Working Group for Sch. Castes and the Report of the Working Group for Sch. Tribes was forwarded to all Central Ministries, Stale Governments! Ut Admns, with the hope that they would appreciate the tenor and spirit of the recommendations made in the Reports and would implement the recommendations effectively. The Reports had been approved by the Steering Group of the Planning Commission. The Actual status of acceptance and implementation of recommendations of the two Reports in question is being collected from all Ministries and State Governments/Ut Administrations and would be laid on the table of the House.

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भुगतान

*273. **श्री ज्ञनेश्वर मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार निदेशालय द्वारा कृषि संबंधी विशेष अध्ययन के लिए 64 लाख रुपये की राशि का भुगतान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को एक मुश्त किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नियम के अनुसार भुगतान किश्तों में किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने संस्थान की सेवा शर्तों में कोई संशोधन किया है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निदेशालय ने विशेष अध्ययन परियोजनाओं पर कुल कितना धन खर्च किया है और इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां, वास्तविक भुगतान 74.844 लाख रुपये का किया गया था ।

(ख) जी, हां । भुगतान क्रमश: 29.280 तथा 35.564 लाख रुपये की दो किस्तों में किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विशेष अध्ययनों के लिए कुल 200.644 लाख रुपये दिये गये हैं, जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

किये गये विशेष अध्ययनों का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	अध्ययन का क्षेत्र	वर्ष	एजेन्सी का नाम	कुल लागत
1.	कृषि विस्तार को ज़ोर करना स्वैच्छिक एजेन्सियों की सहभागिता	1991	सहभागिता और विकास केन्द्र, नई दिल्ली	4.07
2.	महिलाओं को कृषि में लगाना।	1991	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	4.17
3.	विस्तार कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त वापसी जानकारी और अनुसंधान पर इसका प्रभाव	1991	राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थव्यवस्था अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	4.00
4.	विस्तार के लिये अनुसंधानात्मक सहायता तथा उसे मजबूत बनाने के लिये संस्थागत व्यवस्था संबंधी सुझाव	1991	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर	2.30
5.	भारत में प्रशिक्षण और दौरा पद्धति के अन्तर्गत निम्नतम स्तर के विस्तार कर्मचारियों और अनुबंधात्मक किसानों का संचार व्यवहार	1991	राष्ट्रीय संचार विकास परिषद, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	3.40
6.	राज्यों में प्रशिक्षण और दौरा पद्धति आरम्भ करने से पहले और बाद को आदान खपत और उत्पादन की प्रवृत्तियां	1991	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	3.35
7.	कृषि विस्तार के लिये मुद्रित और जन प्रचार माध्यम सहायता प्रशिक्षण और दौरा	1991	भारतीय जन संचार संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर, नई दिल्ली	4.07
8.	राज्यीय मानिटरिंग और मूल्यांकन इकाइयों का संचालन	1991	कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	4.56

क्र.सं.	अध्ययन का क्षेत्र	वर्ष	एजेन्सी का नाम	कुल लागत
9.	(i) जीव वनस्पति और संचरण क्षमता पर अध्ययन (ii) जल ग्रहण क्षेत्र प्राथमिकीकरण/उपचार केन्द्र	1991 और 1992	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	64.844
10.	कृषि अनुसंधान और विस्तार पद्धतियों में किसानों की सहभागिता	1993	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबन्ध संस्थान, हैदराबाद	15.05
11.	फल और सब्जी विपणन	1994	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	90.77

Dumping of drugs

*274. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 25 bulk drug manufacturing units in Karnataka have closed down in the last two years due to unchecked dumping of bulk drugs in the country by China;

(b) whether it is a fact that this has resulted in over 3000 people losing their jobs and investment worth nearly Rs. 100 crores; and

(c) what steps Government have taken to check this onslaught on our drug manufacturers?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) The Government has not received any anti dumping petition from any bulk drug manufacturing unit in Karnataka alleging dumping of bulk drugs by China. The State Government of Karnataka has also not reported closure of any bulk drug manufacturing unit in Karnataka on-account of any dumping of bulk drugs by China.

(b) and (c) Do not arise.

हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोला जाना

***375. श्री महेश्वर सिंह:**
श्री शिवचरण सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सांसदों और अन्य जन-प्रतिनिधियों ने सरकार से केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का अनुरोध किया है ;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय/नवोदयब विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) उपरोक्त में से राज्य-वार किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोले गए हैं और किन-किन स्थानों पर ऐसे विद्यालय खोला जाना सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश में भी नए केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय खोलने का अनुरोध सांसदों से प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो कब और किन-किन